मुख्य परीक्षा

भारत की 'नई रक्षा खरीद नीति, 2016' की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें तथा ये नीति किस प्रकार भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होगी? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

Mention the key features of the India's new 'Defence Procurement Policy' 2016. Critically evaluate how this policy would be successful in fulfulling the defence requirement of India.
(250 Words)

मॉडल उत्तर

उत्तर- भूमिका-

भारत सरकार द्वारा भारत में रक्षा तकनीकों के खरीद संबंधी समस्याएँ यथा धीमापन, सरकारी कंपनियों के एकाधिकार और खरीद प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 2016 को नई रक्षा खरीद नीति लागू की गई। यह नीति फास्ट ट्रैंक प्रक्रिया के पालन तथा देशी तकनीकी को बढ़ावा व रक्षा क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम उपक्रमों को प्रोत्साहित करेगी।

प्रमुख विशेषताएं

- इस नीति के तहत भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसमें मेक इन इंडिया, छोटी ईकाइयों और सेना की जरूरतों को मुख्य आधार बनाया गया है तथा रक्षा खरीद को 5 भागों में बाँटा गया है।
- इस नीति में कंपनियों द्वारा नियुक्त एजेंट को विधिक दर्जा दिया जाएगा तथा कंपनी को एजेंट का नाम सार्वजनिक करना होगा और किए गए भुगतान को भी बताने होंगे जिससे रक्षा खरीद में पारदर्शिता आएगी।
- ऑफसेट के लिए न्यूनतम खरीददारी की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया जो पहले 300 करोड़ था तथा निवेश भारत में 100 प्रतिशत FDI लिमिट में होगा।
- इसने रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2013 का स्थान लिया है तथा इसमें छोटी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इससे खरीददारी को निश्चित किया गया है।
- इससे हथियारों के लिए भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और रक्षा उपकरणों की खरीद देश में ही की जा सकेगी तथा रक्षा खरीद प्रक्रिया से जुड़ा मैन्युअल हर दो महीने में अपडेट होगा।
- देश में रक्षा क्षेत्र में R & D बढ़ाने के लिए अनुसंधान विकास कोष तैयार किया जाएगा।
- यह नीति नई ब्लैकलिस्टिंग नीति को भी जारी करती है तथा पूर्व से ब्लैंक लिस्टेड कंपनियों को कोई रियायत नहीं देने का प्रावधान करता है जिससे खरीद प्रक्रिया विश्वसनीय व त्वरित होगी।

जहाँ एक ओर नई रक्षा खरीद नीति भारत की सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर बनाई गई है वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। एकल वेंडर प्रणाली भ्रष्टाचार व एकाधिकार को बढ़ावा दे सकता है तथा शोध पर खर्च बढ़ाया नहीं गया है तो ऐसे में तकनीकी रूप से पिछड़ापन हो सकता है जो भारत की सुरक्षा जरूरतों को प्रभावित करेगी।